Daily Current Affairs

भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए द्विपक्षीय अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

- भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए ।

समझौता के निष्कर्ष

- इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) इस पूरे अनुबंध अवधि (अगले 10 वर्षों तक) के दौरान बंदरगाह का प्रबंधन और संचालन करेंगा ।
- इस कार्य के लिए लगभग 120 मिलियन डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा गया है ।
-
-

भारत के लिए समझौता का महत्व

- ईरान के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट तक आसान पहुँच प्रदान करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- यह दीर्घकालिक समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ती भूमिका को मजबूत करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह बंदरगाह भारतीय वस्तुओं के लिए भू-आबद्ध अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों तक पहुंचने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा।
- उदाहरण के लिए वर्ष 2023 में, भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की सहायता भेजी थी ।

चाबहार बंदरगाह की अवस्थिति

- चाबहार एक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर स्थित है।
- यह ओमान की खाड़ी के बगल में और होर्मुज जलडमरूमध्य के मुहाने पर है।
- यह हिंद महासागर तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह है और इसमें शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्टी नाम के दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं।
- यह ईरानी बंदरगाहों में भारत के सबसे करीब है , और खुले समुद्र तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे बड़े मालवाहक जहाजों को सुविधा मिलती है ।
- चाबहार की रणनीतिक स्थिति, पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में और ग्वादर के प्रतिस्पर्धी बंदरगाह के करीब (लगभग 72 किमी पश्चिम में) स्थित है, जो इसे भारत के लिए आकर्षक बनाती है।

भारत-ईरान चाबहार बंदरगाह समझौते की समयरेखा

- **1970 -1980 के दशक:** आधुनिक चाबहार के विकास की कल्पना 1970 के दशक में शुरू हुई। 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान को बंदरगाह के रणनीतिक महत्व का एहसास हुआ।
- **जनवरी 2003:** तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति खातमी और तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक सहयोग के एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चाबहार बंदरगाह का विकास भी शामिल था।
- **2004-2015:** अमेरिका ने इराक और उत्तर कोरिया के साथ ईरान को "ऐक्सिस ऑफ एविल" में से एक घोषित किया। इसने नई दिल्ली को तेहरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जिससे चाबहार परियोजना प्रभावित हुई।
- **मई 2015:** संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) पर हस्ताक्षर करने के बाद, जिसने ईरान और P5+1 के बीच संबंध सामान्य कर दिए, चाबहार बंदरगाह के विकास को एक नई गति दी गई। [P5+1 देश ईरान

परमाणु समझौते पर एक साथ काम करने वाले देशों का एक समूह है। इन देशों में जर्मनी के अलावा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हैं। भारत-ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर समझौता हुआ; भारत शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल के नवीनीकरण और 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग सुविधा के पुनर्निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा।

- **मई 2016:** अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, भारत के शिपिंग मंत्रालय ने चाबहार परियोजना को विकसित करने के लिए तीव्र गति से काम शुरू किया।
- **अक्टूबर 2017:** भारत से गेहूं ले जाने वाली पहली खेप अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई।
- **दिसंबर 2017**: ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल का उद्घाटन किया।
- **2018:** जेसीपीओए से अमेरिका के हटने के बावजूद, भारत चाबहार परियोजना के लिए अमेरिका से छूट पाने में कामयाब रहा । भारत ने अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी और चीनी आक्रामक बुनियादी ढांचे का मुकाबला करने को इस प्रयास के प्रमुख कारणों के रूप में बताया।
- **दिसंबर 2018:** भारत ने टर्मिनल क्षेत्र, कार्गो हैंडलिंग और कार्यालय भवन सहित बंदरगाह पर संचालन का कार्यभार संभाला।
- **फरवरी 2019 :** पहला अफगान कार्गो चाबहार बंदरगाह से होकर गुजरा।

चाबहार बंदरगाह का भारत के लिए रणनीतिक महत्व

भूराजनीतिक महत्व

मानवीय सहायता को बढ़ाना- कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय सहायता वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका

राजनयिक संबंधों को मजबूत करना- चाबहार बंदरगाह ने भारत और उसके पश्चिम एशियाई पड़ोसियों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, भारत ने 2021 में टिड्डियों के हमलों से निपटने के लिए बंदरगाह के माध्यम से ईरान को 40,000 लीटर पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक (मैलाथियान) प्रदान किया।

चीनी बुनियादी ढांचे के विस्तार को कम करना- चाबहार परियोजना मध्य और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में चीन के आक्रामक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए एक रणनीतिक असंतुलन के रूप में कार्य करती है, खासकर बेल्ट और रोड जैसी पहल के माध्यम से। उदाहरण के लिए, यह पाकिस्तान में चीन द्वारा ग्वादर बंदरगाह के विकास के प्रतिकार के रूप में कार्य करता है।

भू-आर्थिक महत्व

चाबहार बंदरगाह पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है।

यह बंदरगाह अप्रयुक्त बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके, भारत के लिए मध्य एशिया में अपनी पहुंच का विस्तार करने और बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं में शामिल होने के नए अवसर प्रदान करता है।

भू-रणनीतिक महत्व

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए एक मूल्यवान प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो पाकिस्तान द्वारा भारत की भूमि पहुंच में बाधा के कारण एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

आईएनएसटीसी को पूरक बनाकर, चाबहार बंदरगाह रूस और यूरेशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है, और अधिक क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है।

चाबहार बंदरगाह के साथ, भारत आयात मार्गों में विविधता लाकर, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करके अपने तेल और गैस क्षेत्र में रणनीतिक लाभ प्राप्त करता है।

चाबहार परियोजना की चुनौतियाँ

- हालिया समझौता होने के बाद से ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने चेतावनी दी है कि तेहरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले "किसी को" भी "प्रतिबंधों के संभावित जोखिम" के बारे में पता होना चाहिए। इस कारण आशंका जताई जा रही है कि चाबहार सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं।
- लंबे समय से चल रहे यूक्रेन में युद्ध और रूस के साथ यूरोप के नकारात्मक संबंधों ने INSTC के साथ चाबहार बंदरगाह के एकीकरण को जटिल बना दिया है।
- ईरान और इज़राइल तथा सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव भी चाबहार परियोजना के सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी भू-राजनीतिक चुनौती है।
- ईरान पर कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान से भारत के ऊर्जा आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ये प्रतिबंध चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी)
इस परियोजना का उद्देश्य भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है।
यह दक्षिण एशिया और उत्तरी यूरोप के बीच एक वैकल्पिक और अधिक कुशल व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है और उत्तरी और पश्चिमी यूरोप तक फैला हुआ है।
इस ऐतिहासिक मार्ग का उपयोग यूरोप, भारत और अन्य क्षेत्रों के विभिन्न व्यापारियों द्वारा मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए किया गया है।
वर्तमान INSTC परियोजना की पहल रूस, भारत और ईरान द्वारा सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी।
इस आधुनिक परिवहन मार्ग में शिपिंग, रेल और सड़क परिवहन के संयोजन के माध्यम से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल की आवाजाही शामिल है।
गलियारे का मुख्य लक्ष्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान और बंदर अंजली जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
वर्तमान सदस्य भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, तुर्की, यूक्रेन और बुल्गारिया (पर्यवेक्षक) हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक संतुलनकारी कार्य करने और क्षेत्र में अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है।

एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, भारत दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं रह सकता है और एक शांतिपूर्ण विस्तारित पड़ोस (ईरान-अफगानिस्तान) न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छा है , बल्कि एक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।